

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या : ..... /सम्ब./ 2020

दिनांक : .....

प्रेषक,

कुलसचिव,  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ-226007

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य  
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,  
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

अति आवश्यक

विषय:-रिट याचिका संख्या 7500/2020 दीपेन्द्र विक्रम सिंह, बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शैक्षणिक संस्थाओं के भवन व परिसर में संचालित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों यथा-विवाह, समारोह, कोचिंग सेन्टरों के संचालन एवं दुकानों को प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जाय। यदि किसी भी राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शैक्षणिक संस्थाओं में उक्त से सम्बन्धित मामला प्रकाश में आता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)  
कुलसचिव

संख्या :

AF 11117-20

दिनांक :

06/07/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
3. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल।

5- निदेशक - IPPR.

(वी०पी० कौशल)  
उपकुलसचिव(सम्ब.)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ० प्र०,  
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,  
प्रयागराज।

सेवा में,

1-कुलसचिव

समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2-कुलसचिव,

समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

3-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

उत्तर प्रदेश।

4- समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश

कुल सचिव का कार्यालय

आफ प्राप्ति

संख्या 3388

तिथि 11/06/2020

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ-226007

पत्रांक: डिग्री विकास/ 283-86 / 2020-21 दिनांक: 9/6/2020

विषय:- रिट याचिका संख्या 7500/2020 दीपेन्द्र विक्रम सिंह, बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संलग्न शासन के पत्र सं. मु०.स०-03/सत्तर-6-2020 उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 18 मई 2020 जो रिट याचिका संख्या 7500/2020 दीपेन्द्र विक्रम सिंह, बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2020 के अनुपालन में राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के भवन व परिसर में संचालित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों यथा-विवाह, समारोह, कोचिंग सेन्टरों के संचालन एवं दुकानों को प्रतिबन्धित करने के संबंध में है। शासन के संलग्न पत्र के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जाय। यदि किसी भी राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में उक्त से संबंधित मामला प्रकाश में आता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

*[Signature]*

DR - Legal

*[Signature]*

Registrar

10/6/2020

उपकुलसचिव (विश्वविद्यालय)

कृ० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रतिबन्धित कर  
अनुपालन करना है कि लखनऊ के पत्र निर्गत दिनांक 18 मई  
2020 के शासकीय (स० 03/सत्तर) के निर्देशित करना - यह

Y.C.A.  
10.6.2020

भवदीय

*[Signature]*

डा० (वन्दना शर्मा)

शिक्षा निदेशक (उ०श०), उ०प्र०,

प्रयागराज।



Case :- WRIT - C No. - 7500 of 2020

**Petitioner :-** Deependra Vikram Singh

**Respondent :-** State Of U.P. And 8 Others

**Counsel for Petitioner :-** Vinod Kr Pandey

**Counsel for Respondent :-** C.S.C.

**Hon'ble Ashok Kumar,J.**

Heard learned counsel for the petitioner and Sri Ved Prakash Shukla, learned standing counsel.

By means of the present writ petition the petitioner has prayed for issuance of mandamus directing the respondents to constitute a committee headed by a responsible senior authority for instituting an inquiry and to take necessary action against the respondent nos. 5 to 9 as they permitted and allowed the play ground and the premises of the colleges/ institutions to be used other than educational purposes that is for commercial purposes. Learned counsel for the petitioner has further prayed to direct the respondent nos. 5 to 9 not to operate the shops, marriage ceremonies/ functions and private coaching within the institutions premises in question.

Brief facts of the case are that the petitioner is a member of a society which is registered as Kshatriya Sthaniya Sabha, Jaunpur. The said society is looking after the affairs of the institutions which are managed by the society Kshatriya Sthaniya Sabha, Jaunpur. The petitioner being a member of the society has approached the District Magistrate/ Collector, District Jaunpur, District Inspector of Schools, District Jaunpur and communicated them that in the aforesaid institutions, namely Tilakdhari Inter College, District Jaunpur, and Tilakdhari Post Graduate Degree College, District Jaunpur the management is permitting and allowing for non-educational activities, like permitting the private persons to use the property of the institutions to run the shops and further to use the play ground of the institutions for the purposes of marriage functions/ceremonies and other commercial activities.

A representation dated 8.11.2018 addressed to the District Magistrate, Jaunpur is placed on record as Annexure-1 to the writ petition.

Learned counsel for the petitioner has placed reliance of Annexure 2, which is a Government Order dated 29th September 2012. The contents of said Government Order reads

as follows :

"संस्कृत शिक्षा अनुभाग

संख्या 960/15-9-12-2003 (86) / 2012

लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2012

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश में उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के भवन / परिसर का उपयोग शिक्षण कार्य एवं सहगामी क्रिया कलाप यथा -विद्यार्थियों के खेलकूद तथा व्यक्तित्व विकास आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विवाह समारोहो निजी संस्थाओं एवं कोचिंग सेन्टरों को संचालित करने जैसी गतिविधियों के उपयोग में लाया जा रहा है।

उक्त गतिविधियों से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण एवं पठन पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना को देखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के भवन व परिसर में विवाह समारोह एवं कोचिंग सेन्टरों के संजालन को प्रयोग में न लाया जाय।

पार्थ सारथी सेन शर्मा

सचिव।

संस्था- संख्या 960/15-9-12 तददिनांक"

Learned counsel for the petitioner submits that the respondent no.7 and respondent no.8 institutions are government aided institutions therefore while permitting other than educational activities and sports activities the management of the aforesaid institutions are not only collecting the money but are clearly disobeying the Government Order dated 29th September 2012 and are prohibiting the students of the institutions to use the play ground of the institutions for their playing activities/ sports activities.

Since the issue raised by the petitioner is happening in many of the Government aided institutions and other educational institutions throughout the State of U.P., as is seen by everyone and in every township/city, this Court deem it appropriate to direct the Chief Secretary, Government of U.P. and the Principal Secretary (Education) Government of U.P. to issue an appropriate order to all the District Magistrates of State of U.P. to ensure the true compliance of the Government Order dated 29th September 2012, which prohibits any commercial activities on the properties belongs to educational institutions.



The land and building of the school is reserved and is only used for activities connected with teaching and sports for the students. The land appurtenant to the school should not be permitted to be used for any activity other than activities of the school.

The Chief Secretary, Government of U.P. and the Principal Secretary (Education) Government of U.P. will issue the appropriate orders within two weeks from today and will ensure the true compliance of the Government Order dated 29th September 2012.

In view of the aforesaid, this Court direct all the District Magistrate of State of U.P. to call for the explanations from the institutions and to direct them to furnish the details as to how and when they permitted the commercial activities in their institutions particularly the use of play ground which is exclusively meant for the students of the institutions for sports activities.

As prayed by learned standing counsel three weeks' time is allowed to file the counter affidavit. One week thereafter for filing rejoinder affidavit.

As an interim measure I direct to the respondents and all the District Magistrates of all the Districts of U.P. to restrain all educational institutions to allow anyone to use the property of the institutions for any private purpose. No marriage function or commercial activities to be organized on the land and building of the schools/ colleges/ institutions. This order, however, will not come in the way of using the land exclusively for the purpose of academic and sports activities of the schools and the colleges.

List this petition before this Court on 31.3.2020.

A copy of this order will be provided to the Chief Secretary, Government of U.P. and the Principal Secretary (Education) Government of U.P. by learned standing counsel within three days.

Order Date :- 3.3.2020  
S.S.